नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

5 डिजिटल भारत में उपभोक्ता न्याय के लिए नई परिकल्पना

6 विवेकपूर्ण जीवन का आध्यात्मिक रहस्य

7 ज्योतिष और मानव सभ्यता का भविष्य

8 कोलंबिया ने राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई

आतंकवाद पर बड़ा प्रहार

शाह बोले- हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करेगी सरकार

नई दिल्ली, 04 जुलाई. आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 23 और व्यक्तियों को गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत 'आतंकवादी' घोषित किया है.

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार भारत और देशवासियों की सुरक्षा के लिए हर आतंकी मॉड्यूल को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है. घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में 17 पाकिस्तानी और 6 भारतीय नागरिक हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओके) से भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं.

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' विजन को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 23 खूंखार आतंकवादियों को यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है.

ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, आतंकी हमलों, आतंकवाद को बढ़ावा देने, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकी संगठनों की मदद, फंड जुटाने और आतंकवादियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं. मोदी सरकार भारत और देशवासियों की सुरक्षा के लिए हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए कटिबद्ध है।

गृह मंत्रालय के अनुसार, इन व्यक्तियों को औपचारिक रूप से आतंकवादी घोषित किए जाने से उनके वित्तीय नेटवर्क, आवाजाही, भर्ती क्षमता और आतंकवाद समर्थित गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी. साथ ही यह कदम राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल तत्वों के लिए कड़ा संदेश भी होगा.

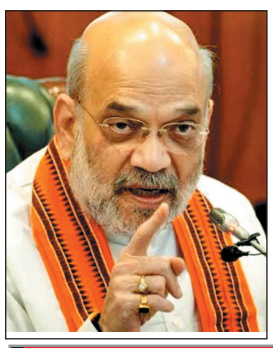

23 व्यक्तियों को किया गया आतंकवादी घोषित

गृह मंत्रालय ने जिन 23 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है, उनमें मसूद इलियास कश्मीरी, मोहम्मद मुसादिक, मुफ्ती मोहम्मद असगर खान, हाफिज अब्दुल शकूर, अब्दुल्ला जिहादी, फिरदौस अहमद भट, गुलाम फरीद, हारून रशीद गनई, बिलाल अहमद मीर, आबिद कयूम लोन, नजीर अहमद गुज्जर, अब्दुल रऊफ, अशफाक अहमद, हाफिज खालिद वालीद, मौलाना इमदाद उल्लाह मक्की, मौलाना सैफुल्लाह खालिद, मोहम्मद याकूब, मौलाना यूसुफ ताईबी, ओवैस फारूज, कारी याकूब शेख, राणा इफ्तिखार, वसीम नूर जाट और मोहम्मद शहीद फैसल शामिल हैं.

गृह मंत्रालय द्वारा घोषित 23 आतंकवादियों में अधिकांश का संबंध जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम), लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जमात-उद-दावा (जेयूडी), हरकत-उल-मुजाहिद्दीन (एचयूएम), पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (पीएमएमएल), अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से है. इन पर सीमा पार घुसपैठ, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी, ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाने, आतंकी फंडिंग, युवाओं की भर्ती, प्रशिक्षण शिविर संचालित करने और भारत में कई बड़े आतंकी हमलों की साजिश रचने या उन्हें अंजाम देने के आरोप हैं.

संकट में भी जनता पर नहीं पड़ने दिया बोझ

प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान रिफाइनरी राष्ट्र को किया समर्पित

1.06 लाख करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन

जोधपुर/बालोतरा(राजस्थान) 04 जुलाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जोधपुर और बालोतरा में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और देश की ऊर्जा नीति, कूटनीति तथा जल प्रबंधन पर विस्तृत विचार साझा किए.

उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और बाद में बालोतरा स्थित पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण कर उसे देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. सुबह लगभग 10:40 बजे प्रधानमंत्री जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने 'उड़ान-2.0' योजना की भी शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को और अधिक मजबूत बनाना है.

राजस्थान के बालोतरा से 1.06 लाख करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया. इन परियोजनाओं में ऊर्जा, जल, परिवहन, विमानन और कनेक्टिविटी से जुड़े कई प्रमुख कार्य शामिल हैं. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.

एसआईटी ने बैंक रिकॉर्ड खंगाले व बैंक कर्मियों से की पूछताछ

अयोध्या, 4 जुलाई. अयोध्या स्थित राम मंदिर में दान राशि से जुड़े कथित गबन प्रकरण की जांच आगे बढ़ रही है. विशेष जांच दल (एसआईटी) अब मंदिर ट्रस्ट के बैंक खातों में जमा होने वाली दैनिक राशि, नकदी जमा प्रक्रिया और संबंधित वित्तीय रिकॉर्ड की विस्तृत जांच कर रहा है। बैंक खातों में जमा राशि के आंकड़ों में अंतर सामने आने के बाद एसआईटी ने इसे जांच का महत्वपूर्ण आधार बनाया है। हालांकि, प्रतिदिन कथित रूप से किसी निश्चित राशि की हेराफेरी होने संबंधी दावे अभी जांच के दायरे में हैं.

सचिन का 37 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा

सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी बने वैभव

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट को एक नया सितारा मिल गया है। महज 15 साल 99 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के लिए डेब्यू करते ही इतिहास रच दिया।

इसके साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत की ओर से सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल कर लिया। सचिन ने 1989 में 16 साल 205 दिन की उम्र में पाकिस्तान के

खिलाफ अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। युवा बल्लेबाज वैभव को कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम में संजू सैमसन की जगह मौका मिला। आयरलैंड दौरे पर टीम में शामिल होने के बावजूद उन्हें डेब्यू का अवसर नहीं मिला था, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले में इंतजार खत्म हुआ। टॉस के दौरान कप्तान श्रेयस अय्यर ने वैभव की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से प्रभावित करने वाले वैभव से अब भारतीय टीम को भी बड़ी उम्मीदें हैं। क्रिकेट जगत की निगाहें इस किशोर बल्लेबाज पर हैं, जिसने डेब्यू से पहले ही इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा दिया।

एक नजर में

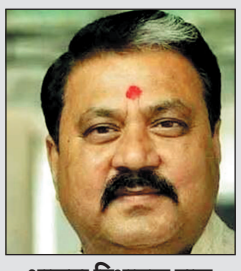

भाजपा विधायक राजू सिंह को 4 साल की सजा

नई दिल्ली. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के साहेबगंज (मुजफ्फरपुर) से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक राजू कुमार सिंह को वर्ष 2018 में हुई हर्ष फायरिंग की घटना में महिला डॉक्टर की गैर इरादतन हत्या के मामले में चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी विधायक को पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता पर प्रभाव पड़ सकता है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने इससे पहले विधायक राजू कुमार सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-दो) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत दोषी ठहराया था।

सरकार ने प्याज खरीद मूल्य 250 रुपए बढ़ाया

नई दिल्ली. द्वकेंद्र ने मूल्य स्थिरीकरण योजना के तहत प्याज का सरकारी क्रय मूल्य 13 प्रतिशत (250 रुपये) बढ़ा कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है जो शनिवार से ही प्रभावी हो गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश में प्याज की कोई कमी नहीं है पर वर्षा में देरी से प्याज की रोपाई महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ इलाकों में धीमी चल रही है। इससे खास कर प्याज की बड़े स्तर पर खेती करने वाले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों के किसानों को बेहतर मुनाफा मिलेगा और खरीदारी बढ़ेगी। सरकार प्याज जैसी कुछ फसलों के दामों पर तेज उतार-चढ़ाव के दौर में किसानों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए मूल्य स्थिरीकरण योजना के तहत बफर स्टॉक रखती है।

ओटीटी कंटेंट व फ्री वेब सीरीज पर लगेगी रोक

नई दिल्ली, 04 जुलाई. केंद्र सरकार ने डिजिटल पायरेसी पर बड़ा कदम उठाते हुए टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों, वेब सीरीज और ओटीटी कंटेंट के प्रसार पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि कंपनी अगले 15 दिनों के भीतर ऐसे सभी चैनलों, ग्रुप्स, बॉट्स और अकाउंट्स के खिलाफ की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे. सरकार ने टेलीग्राम को साफ शब्दों में कहा है कि वह केवल शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करने की नीति पर निर्भर न रहे. कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म पर पायरेटेड सामग्री की पहचान और उसे रोकने के लिए प्रभावी तकनीकी व्यवस्था विकसित करनी होगी. मंत्रालय का मानना है कि वर्तमान व्यवस्था सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुरूप पर्याप्त नहीं है. सरकार ने बार-बार कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन करने वाले चैनलों, ग्रुप्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और उनसे जुड़े नेटवर्क के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. इससे पहले भी पायरेसी फैलाने वाले 3,000 से अधिक टेलीग्राम चैनलों पर कार्रवाई की जा चुकी है. सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में भी इस तरह का कंटेंट मिलता है तो और सख्त कदम उठाए जाएंगे. यह नोटिस ऐसे समय आया है जब हाल ही में सरकार ने टेलीग्राम के यूजरनेम फीचर को लेकर भी सवाल उठाए हैं.

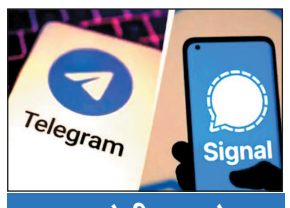

अब टेलीग्राम को सरकार का नोटिस

समिति ने 11 बिंदुओं पर कीं अनुशंसाएं

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 4 जुलाई. मप्र विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में समिति प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित पीठासीन अधिकारियों की समिति की अंतिम बैठक पश्चिम बंगाल विधानसभा कोलकाता में संपन्न हुई. तीन समीक्षा बैठकों में चर्चाओं के बाद समिति ने 11 बिंदुओं पर अनुशंसाएं की हैं.

इन सिफारिशों के साथ समिति का प्रतिवेदन सात राज्यों के अध्यक्षों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा गया. प्रतिवेदन सौंपते समय सात राज्यों के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर अध्यक्ष मप्र विधानसभा, सतीश महाना अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधानसभा, वासुदेव देवनानी अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा, कुलदीप सिंह पठानिया अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधानसभा, रथीन्द्र नाथ बोस अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल विधानसभा, मिंग्मा नोर्बु शेरपा अध्यक्ष, सिक्किम विधानसभा तथा श्रीमती सुरामा पाढी अध्यक्ष, ओडिशा विधानसभा मौजूद थे. गौरतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायी कार्यवाही में वित्तीय सहित तदर्थ समितियों की भूमिका के महत्व को रेखांकित किया है. इस भूमिका को अधिक स्पष्ट और समर्थ बनाने के लिए गठित समिति की अध्यक्षता मप्र के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपी गई थीं.

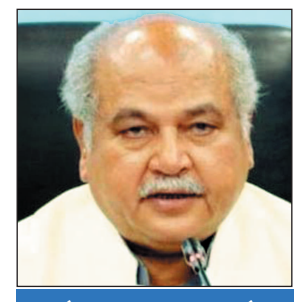

लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा गया प्रतिवेदन

मिशिगन के शॉपिंग मॉल में गोलीबारी में दो लोगों की मौत

वाशिंगटन,04 जुलाई. अमेरिका के मिशिगन राज्य में एक शॉपिंग मॉल में हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। स्थानीय पुलिस के हवाले से यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि यह गोलीबारी शुक्रवार को दोपहर करीब 1:25 बजे मिशिगन के डियरबॉर्न में फेयरलेन टाउन सेंटर में हुई। बाद में पुलिस ने बताया कि दो लोगों को डियरबॉर्न पुलिस विभाग ने हिरासत में लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, मामले की जांच चल रही है और जासूस गवाहों से पूछताछ कर रहे हैं.

भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू

- आर्थिक साझेदारी को मिलेगी नई मजबूती
- निवेश माहौल सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम

नई दिल्ली, 04 जुलाई. भारत गणराज्य की सरकार और इजराइल की सरकार के बीच 8 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश समझौता शनिवार, 4 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गया.

इस समझौते को दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा पूर्वानुमानित निवेश माहौल सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. द्विपक्षीय निवेश समझौता निवेशकों और उनके निवेशों को मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है. साथ ही, यह दोनों देशों को अपने वैध सार्वजनिक नीति उद्देश्यों के अनुरूप संप्रभु नीतिगत अधिकार बनाए रखने का पर्याप्त लचीलापन भी देता है. यह समझौता अंतरराष्ट्रीय निवेश कानून के आधुनिक सिद्धांतों और विकसित होते न्यायशास्त्र के अनुरूप तैयार किया गया है।

बीएलओ हैं लोकतंत्र की नींव : ज्ञानेश

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सराहा मध्यप्रदेश का एसआईआर अभियान

नवभारत न्यूज़

इंदौर, 4 जुलाई. भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने शनिवार को इंदौर में बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ से संवाद करते हुए मध्यप्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान की सराहना की।

उन्होंने कहा कि राज्य ने इस अभियान को पारदर्शी, व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से पूरा कर देश के लिए आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि बीएलओ लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे घर-घर पहुंचकर नए मतदाताओं का पंजीयन, मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट एवं अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने सहित मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उन्होंने विशेष रूप से दूरस्थ आदिवासी और वन क्षेत्रों में कार्यरत बीएलओ के समर्पण की सराहना की।

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली विश्व की सबसे पारदर्शी और विश्वसनीय प्रणालियों में शामिल है। देश में करीब 95 करोड़ मतदाता हैं और चुनाव प्रक्रिया के संचालन में लगभग 1.80 करोड़ चुनावकर्मी भागीदारी निभाते हैं।

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक

नई दिल्ली, 04 जुलाई. संसद का मानसून सत्र आगामी 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा और इस दौरान करीब 19 बैठकें होनी की संभावना है. संसदीय कार्य मंत्री किरेण रिजिजू ने शनिवार को यह जानकारी दी।

श्री रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से बुलाने की मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा ,सरकार की सिफारिश पर

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संसद के दोनों सदनों का मानसून सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है। यह सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे।

बदहाली | ग्रामीणों ने अधजले शव को निकालकर दोबारा किया दाह संस्कार

तेज बारिश में अंतिम संस्कार के दौरान बह गई चिता

संजय बाजपेई

धार. विकास के दावों और सरकारी योजनाओं की चमक के बीच आदिवासी अंचल की एक ऐसी दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जिसने व्यवस्था की संवेदनहीनता को बेनकाब कर दिया है. धार जिले के जामला गांव में एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार के दौरान अचानक उफनाए नाले में जलती चिता बह गई. परिजनों और ग्रामीणों की आंखों के सामने अधजला शव तेज बहाव में बहने लगा. मजबूर ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर शव को बाहर निकाला और दूसरी जगह चिता सजाकर अंतिम संस्कार पूरा किया.

यह घटना नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के विधानसभा क्षेत्र की है, जहां वर्षों से विकास के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन आज भी ग्रामीणों को सम्मानजनक अंतिम संस्कार जैसी बुनियादी सुविधा तक नसीब नहीं है.

मुखाग्नि के कुछ देर में ही बह गया शव

ग्राम जामला के खाड़ापुरा मोहल्ले के निवासी बुजुर्ग बापूसिंह के निधन के बाद परिजन उन्हें गांव के मुक्तिधाम लेकर पहुंचे. मुखाग्नि दिए जाने के कुछ ही समय बाद पास का पहाड़ी नाला अचानक उफान पर आ गया. देखते ही देखते पानी का तेज बहाव चिता को अपने साथ बहाकर ले गया. परिजन और ग्रामीण स्तब्ध रह गए. गम और बेबसी के बीच कुछ ग्रामीण पानी में उतरे और अधजले शव को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर दोबारा चिता तैयार कर अंतिम संस्कार कराया.

सुलगते सवाल

सवाल यह है कि जिस मुक्तिधाम का निर्माण हुआ, वह आखिर उफनते नाले के किनारे क्यों बनाया गया? क्या निर्माण से पहले सुरक्षा और भौगोलिक परिस्थितियों का आकलन नहीं किया गया? यदि बारिश के मौसम में अंतिम संस्कार तक सुरक्षित नहीं हो सकता, तो ऐसे विकास कार्यों का औचित्य क्या है?

ग्रामीणों में गहरा आक्रोश

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि ग्राम पंचायत के जिम्मेदार प्रतिनिधि इस पूरे मामले से चुप नजर आए. सरपंच प्रतिनिधि कैलाश भंवर ने घटना की विस्तृत जानकारी होने से इनकार करते हुए केवल इतना कहा कि उन्हें गांव में एक बुजुर्ग की मृत्यु की सूचना थी. घटना के बाद ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है. उनका कहना है कि जीवित रहते हुए सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है और मृत्यु के बाद भी सम्मानजनक विदाई नसीब नहीं होती. ग्रामीणों ने मांग की है कि गांव में बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित स्थान पर स्थायी और सुरक्षित मुक्तिधाम का निर्माण कराया जाए,